सी.एन. अरुणाचला मुदलियार

बनाम

सी.ए. मुरुगनाथा मुदलियार और एक अन्य

(मेहर चंद महाजन, मुखर्जी और जगन्नाथदास जेजे.)

हिंदू-कानून-उपहार-पिता द्वारा बेटे को उपहार में दी गई संपत्ति-बेटे के हाथों में पैतृक संपत्ति- वसीयत का निर्माण।

एक पिता द्वारा अपने बेटे को उपहार में दी गई संपत्ति केवल इस तथ्य के कारण बेटे के हाथों में पैतृक संपत्ति नहीं बन सकती थी कि उसे यह संपत्ति अपने पिता से मिली थी। जब पिता कोई उपहार देता है तो वह यह स्पष्ट रूप से प्रदान करने के लिए काफी सक्षम होता है कि या तो किया गया व्यक्ति इसे विशेष रूप से अपने लिए लेगा या यह कि उपहार परिवार की उसकी शाखा के लाभ के लिए होगा, और यदि उपहार या वसीयत के विलेख में इस आशय के स्पष्ट प्रावधान हैं, तो ऐसी संपत्ति में बेटा जो ब्याज लेगा, वह अनुदान की शर्तों पर निर्भर करेगा।

यदि इस बात का वर्णन करने के लिए कोई स्पष्ट शब्द नहीं हैं कि किस तरह का ब्याज लिया जाना है, तो सवाल निर्माण का होगा और अदालत को निर्माण के स्थापित नियमों के अनुसार आसपास की परिस्थितियों के साथ लिए गए दस्तावेज़ की भाषा से दाता के इरादे को एकत्र करना होगा। ऐसे मामलों में भौतिक प्रश्न यह होगा कि क्या अनुदानकर्ता वास्तव में अपने बेटे को संपत्तियों का उपहार देना चाहता था या प्रत्यक्ष उपहार केवल इसे विभाजित करने की योजना का एक अभिन्न अंग था।

ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि उन्होंने एक या दूसरे का इरादा किया था, क्योंकि यह पिता के लिए खुला है कि वह उपहार दें या अपनी संपत्तियों को विभाजित करें जैसा कि वह खुद चाहते हैं।

मुद्दिम बनाम राम (6 डब्ल्यू.आर. 71), नागलिंगम बनाम रामचंद्र (आई.एल.आर. 24 मद्रास 429), भागवत बनाम एमएसटी। कपूरनी (आई.एल.आर. 23 पटना 599), जुगमोहन दास बनाम मंगल दास (आई.एल.आर. 10 बॉम्बे 528), परसोत्तम बनाम जानकीबाई (आई.एल. आर. 29 इलाहाबाद 354), अमरनाथ बनाम गुरन (ए.एल.आर.1918 लाह. 394), लाल राम सिंह बनाम उपायुक्त, प्रतापगढ़ (64 आई.ए. 265)।

जहां एक वसीयतकर्ता जिसके 3 बेटे थे, अपनी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों को कुछ संपत्तियां देने के बाद, यह प्रावधान करता है कि वसीयत की अनुसूची ए, बी और सी में संपत्तियां जो उसकी स्व-अर्जित संपत्तियां थीं, वे क्रमशः उसके सबसे बड़े, दूसरे और तीसरे बेटे द्वारा ली जाएंगी, और बेटे उन्हें आवंटित संपत्तियों का पूर्ण अधिकारों और अलगाव की शक्तियों जैसे उपहार, विनिमय, बिक्री आदि का उपभोग करेंगे।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जैसा कि वसीयत में स्पष्ट रूप से पुत्रों को अलगाव की शांत शक्तियों के साथ पूर्ण अधिकार निहित किए गए थे, संपत्ति को उनके अपने पुरुष मुद्दे के खिलाफ उनके हाथों में पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं दिया गया था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 191/1952।

मद्रास उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति राव और न्यायमूर्ति सोमसुंदरम) के 13 दिसंबर, 1949 के निर्णय और डिक्री से 21 मई, 1951 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई विशेष अनुमति द्वारा अपील, 1945 के ओ.एस. संख्या 138 में कोयंबटूर के

अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय के 20 फरवरी, 1946 के निर्णय और डिक्री से उत्पन्न अपील संख्या 529 में।

अपीलार्थी के लिए पी.सोमसुंदरम (उनके साथ आर. गणपति अय्यर)।

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए बी. सोमय्या (उनके साथ के.आर. चौधरी)।

14 अक्टूबर 1953 को न्यायालय का निर्णय मुखर्जी जे. द्वारा दिया गया था।

यह अपील, जो विशेष अनुमति पर हमारे समक्ष आई है, 13 दिसंबर, 1949 को मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के एक फैसले और डिक्री के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें मामूली संशोधन के साथ, 1945 के ओ.एस. संख्या 138 में पारित अधीनस्थ न्यायाधीश, कोयंबटूर के निर्णय की पुष्टि की गई है।

वादी, जो विभाजन पर विशिष्ट आवंटन के लिए इस अपील में प्रतिवादी संख्या 1 है, ने वाद में वर्णित संपत्तियों में अपने एक तिहाई हिस्से का मुकदमा इस आरोप पर शुरू किया था कि वे एक परिवार की संयुक्त संपत्तियां थीं जिसमें वह, उसके पिता, प्रतिवादी संख्या 1 और उसका भाई, प्रतिवादी संख्या 2 शामिल थे और वह उसी में एक तिहाई हिस्से का कानूनी रूप से हकदार था। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी और प्रतिवादी नंबर 2, जो दो भाई हैं, दोनों प्रतिवादी नंबर 1 के बेटे हैं जो उसकी पहली पत्नी से है जो अपने पति से पहले मर गई थी। वादी की माँ की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने फिर से शादी कर ली और उसकी दूसरी पत्नी मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 3 है।वाद में आरोप, सार में यह है कि सौतेली माँ के घर में आने के बाद, पिता और उसके बेटों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए और जैसे ही पिता ने संयुक्त पारिवारिक संपत्ति पर एक विशेष अधिकार का दावा करना शुरू किया, अपने बेटों के किसी भी अधिकार से इनकार करते हुए, वर्तमान मुकदमे को उन संपत्तियों को लाना पड़ा जिनके संबंध में वादी दावा करता है कि विभाजन का वर्णन वाद की अनुसूची बी में किया गया है। इनमें कुल

मिलाकर 5 एकड़ से थोड़ी अधिक कृषि भूमि की चार वस्तुएँ, इरोड शहर में एक आवासीय घर और कुछ आभूषण, फर्नीचर और पीतल के बर्तन शामिल हैं। इनके अलावा शिकायत के पैराग्राफ 11 में यह कहा गया है कि लगभग रु 15,000 इरोड अर्बन बैंक लिमिटेड में पहले प्रतिवादी के नाम पर जमा किए गए; वह पैसा भी संयुक्त परिवार का है और वादी उसमें अपने हिस्से का हकदार है।

प्रतिवादी नं. 1 ने अपने लिखित बयान में वादी के इन सभी आरोपों को तोड़ दिया और इस बात से इनकार किया कि कोई संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी जिस पर वादी दावा कर सकता था। उनका मामला यह था कि अनुसूची बी की भूमि की वस्तु 1 और 2 के साथ-साथ घर की संपत्ति उनके पिता की स्व-अर्जित संपत्ति थी और उन्होंने उन्हें वर्ष 1912 में उनके द्वारा निष्पादित वसीयत के तहत प्राप्त किया था। अचल संपत्ति की अन्य वस्तुओं के साथ-साथ नकदी, फर्नीचर और बर्तन उनके अपने अधिग्रहण थे जिनमें बेटों की कोई रुचि नहीं थी। जहाँ तक वाद में उल्लिखित रत्नों का संबंध है, यह कहा गया था कि उनमें से केवल कुछ ही मौजूद थे और वे विशेष रूप से उनकी पत्नी, प्रतिवादी संख्या 3 के थे।

प्रतिवादी संख्या 2, जो वादी का भाई है, ने वादी के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने लिखित बयान में जोर देकर कहा कि वह मुकदमे में एक आवश्यक पक्ष नहीं थी और जो भी गहने थे वे विशेष रूप से उसके थे। मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल जज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिवादी नंबर 1 को उसके पिता द्वारा विरासत में दी गई संपत्तियों को उसके हाथों में पैतृक संपत्ति माना जाना चाहिए और अन्य संपत्तियों को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अधिग्रहित किया गया था। पैतृक संपत्ति की आय से वे संयुक्त संपत्ति के चरित्र से भी प्रभावित हुए। परिणाम यह हुआ कि अधीनस्थ न्यायाधीश ने वादी के पक्ष में एक प्रारंभिक आदेश दिया और आभूषणों की कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जिन्हें अस्तित्व में नहीं माना गया था, उनके

दावे की अनुमति दी। इस निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी नंबर 1 ने मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने इस परिवर्तन के साथ अपील को खारिज कर दिया कि रत्न-जैसे कि वे मौजूद थे-केवल प्रतिवादी संख्या 3 के थे और फर्नीचर और पीतल के बर्तनों के विभाजन के लिए वादी के दावे को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इस अदालत में अपील करने की अनुमति के लिए प्रतिवादी नंबर 1 के आवेदन को खारिज कर दिया, लेकिन वह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे। अपील में जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता की वसीयत के तहत मिली संपत्तियों को उसके हाथों में पैतृक या स्व-अर्जित संपत्तियों के रूप में माना जाना चाहिए। यदि संपत्तियाँ पैतृक होतीं, तो बेटे उनके संबंध में अपने पिता के साथ सह-मालिक बन जाते और जैसा कि यह स्वीकार किया जाता है कि अचल संपत्ति की अन्य वस्तुएं केवल इस मूल केंद्र के लिए वृद्धि थीं, वादी का दावा सफल होना चाहिए। यदि, दूसरी ओर, वसीयत की गई संपत्तियां प्रतिवादी के हाथों में स्व-अर्जित संपत्तियों के रूप में रैंक कर सकती हैं। ।, वादी का मामला विफल होना चाहिए। इस बिंदु पर कानून, जैसा कि नीचे दी गई अदालतों ने बताया है, काफी समान नहीं है और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा इस पर परस्पर विरोधी राय व्यक्त की गई है, जिनकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। प्रश्न के उचित निर्धारण के लिए, सबसे पहले मिताक्षर में पिता के अपनी स्व-अर्जित संपत्ति पर अधिकार और उसके बेटों या पोते द्वारा लिए गए ब्याज के संबंध में निर्धारित कानून का उल्लेख करना सुविधाजनक होगा। प्लैसिटम 27, अध्याय ।; मिताक्षर की धारा 1 में कहा गया हैः

"यह तय किया गया है कि पैतृक या पैतृक संपत्ति में संपत्ति जन्म से होती है, हालांकि पिता के पास कर्तव्य के अपरिहार्य कार्यों के लिए और स्नेह, परिवार के समर्थन, संकट से राहत आदि के माध्यम से उपहार के रूप में कानून के ग्रंथों द्वारा

निर्धारित उद्देश्यों के लिए अचल वस्तुओं के अलावा अन्य प्रभावों के निपटान में स्वतंत्र शक्ति होती है; लेकिन वह अचल संपत्ति के संबंध में अपने और बाकी के नियंत्रण के अधीन है, चाहे वह स्वयं द्वारा अर्जित की गई हो या अपने पिता और अन्य पूर्ववर्तियों से विरासत में मिली हो क्योंकि यह नियुक्त किया गया है, हालांकि अचल या द्वि-संपत्ति स्वयं मनुष्य द्वारा प्राप्त की गई है, लेकिन सभी बेटों को बुलाए बिना उनका उपहार या बिक्री नहीं की जानी चाहिए।" मिताक्षर एक व्यक्ति के धार्मिक कर्तव्य पर जोर देता है कि वह अपने परिवार को बिना सहारे के न छोड़े और यह कहते हुए पाठ का समापन करता हैः "वे जो पैदा हुए हैं और जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं और जो अभी भी गर्भ में हैं, उन्हें समर्थन के साधनों की आवश्यकता है। इसलिए कोई उपहार या बिक्री नहीं की जानी चाहिए। इस नियम से काफी भिन्न है जो आपको प्रतिबंधित करता प्रतीत होता हैः पिता का अपनी स्व-अर्जित संपत्ति पर अयोग्य तरीके से और उसी तरह से पैतृक भूमि पर निपटान का अधिकार, टिप्पणी में अन्य ग्रंथ पाए जाते हैं जो व्यावहारिक रूप से हस्तक्षेप के किसी भी अधिकार से इनकार करते हैं। अध्याय 1, धारा 5, प्लेसिटम 9 में कहा गया हैः "पोते को निषेध का अधिकार है यदि उसके अलग किए गए पिता दादा से विरासत में मिले प्रभावों का दान या बिक्री कर रहे हैंः लेकिन उसे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है यदि प्रभाव पिता द्वारा प्राप्त किए गए थे। वास्तव में उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह निर्भर है। इस भेद का कारण लेखक द्वारा निम्नलिखित पाठ में समझाया गया हैः "परिणामस्वरूप अंतर यह हैः हालाँकि अपने पिता और अपने दादा की संपत्ति में जन्म से उसका अधिकार है; फिर भी चूंकि वह पैतृक संपत्ति के संबंध में अपने पिता पर निर्भर है और चूंकि पिता का प्रमुख हित है क्योंकि यह स्वयं अर्जित किया गया था, इसलिए बेटे को अपनी अर्जित संपत्ति के पिता के निपटान में सहमति देनी चाहिए।"

स्पष्ट रूप से बाद के परिच्छेद पिछले परिच्छेदों के बिल्कुल विपरीत हैं और कलकत्ता के एक प्रारंभिक मामले (1) में यह विचार रखते हुए एक सुलह का प्रयास किया गया था कि अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में बेटों का अधिकार एक अपूर्ण अधिकार था जो कानून में लागू होने में असमर्थ था। यह प्रश्न राव बलवंत बनाम रानी किशोरी (2) के मामले में न्यायिक समिति के समक्ष विचार के लिए स्पष्ट रूप से आया और बोर्ड का निर्णय देने वाले लॉर्ड हॉबहाउस ने अपने निर्णय के दौरान कहा कि हिंदू कानून पर पाठ्य पुस्तकों और टिप्पणियों में धार्मिक और नैतिक विचारों को अक्सर सकारात्मक कानून के नियमों के साथ मिलाया जाता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि मिताक्षर के अध्याय I, धारा 1, श्लोक 27 में केवल नैतिक या धार्मिक उपदेश हैं जबकि धारा 5, श्लोक 9 और 10 में सकारात्मक कानून के नियम शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप उत्तरार्द्ध पूर्ववर्ती पर हावी हो जाएगा। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि मिताक्षर कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार के पिता के पास अपनी स्व-अर्जित अचल संपत्ति पर स्वभाव की पूर्ण और अनियंत्रित शक्तियां हैं और उनका पुरुष मुद्दा किसी भी तरह से इन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कानून के इस कथन को तब से कभी चुनौती नहीं दी गई है और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है, और हमारी राय में यह सही है कि एक मिताक्षर पिता न केवल अपनी स्व-अर्जित अचल संपत्ति-अपने बेटों की सहमति के बिना किसी अजनबी को बेचने के लिए सक्षम है, बल्कि वह अपनी संपत्ति का उपहार अपने बेटों में से एक को दूसरे के नुकसान के लिए दे सकता है (3) और वह अपने उत्तराधिकारियों के बीच असमान वितरण भी कर सकता है (4)। अब तक कानून निष्पक्ष रूप से सुलझा हुआ प्रतीत होता है और विवाद के लिए कोई जगह नहीं है। हालाँकि, इस सवाल पर विवाद पैदा होता है कि एक बेटा अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में किस तरह का हित लेगा, जो वह उससे उपहार या वसीयतनामा वसीयत के

रूप में प्राप्त करता है, जबकि उसका अपना पुरुष मुद्दा है। (1) द्वारा मुद्दुन बनाम रानी, 6 डब्ल्यू. आर. 71 (2) 25 आई.ए. 54(3) शीतल बनाम माधो, आई.एल.आर.आर. ऑल के माध्यम से 394 (4) बावा बनाम, राजा, 10 डब्ल्यू. आर. 287 क्या यह उसके हाथों में स्व-अर्जित संपत्ति बनी रहती है जो उसके बेटों और पोतों के अधिकारों से भी अछूती है या क्या यह उसके हाथों में पैतृक संपत्ति बन जाती है, हालांकि वंश द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है, जिसमें उसका पुरुष हिस्सा उसके साथ सह-मालिक बन जाता है? इस प्रश्न का उत्तर भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अलग-अलग तरीकों से दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक राय में काफी विविधता आई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय (1) द्वारा वर्ष 1863 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसी संपत्ति उनके बेटे के हाथों में पैतृक संपत्ति के रूप में होती है जैसे कि उन्हें यह अपने पिता से विरासत में मिली हो। अन्य उच्च न्यायालयों में इस प्रश्न को प्रत्येक मामले में इसके तथ्यों के संदर्भ में तय किए जाने वाले निर्माण के रूप में माना जाता है कि क्या उपहार में दी गई संपत्ति का उद्देश्य बेटों को पैतृक या स्व-अर्जित संपत्ति देना था; लेकिन यहां फिर से न्यायिक राय का एक तीखा विभाजन है। मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि (2) यह निस्संदेह पिता के लिए यह निर्धारित करने के लिए खुला है कि उसने जो संपत्ति विरासत में दी है वह पैतृक होगी या स्व-अर्जित, लेकिन जब तक वह अपना इरादा व्यक्त नहीं करता है कि वह स्व-अर्जित होगी, तब तक इसे पैतृक माना जाना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय (3) की पूर्ण पीठ ने मद्रास के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है और इस मुद्दे पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का नवीनतम निर्णय इसकी ओर झुकता प्रतीत होता है (4) दूसरी ओर, बॉम्बे उच्च न्यायालय का विचार है कि दान की गई संपत्ति को स्व-अधिग्रहण के रूप में पुराना किया जाए, जब तक कि दाता की ओर से इसे पैतृक बनाने के इरादे की स्पष्ट अभिव्यक्ति न हो (5), और इस विचार को इलाहाबाद और लाहौर उच्च न्यायालयों (6)

द्वारा स्वीकार किया गया है। न्यायिक राय के इस टकराव को लाल राम सिंह बनाम प्रतापगढ़ के उपायुक्त (7) मामले में प्रिवी काउंसिल के संज्ञान में लाया गया था, लेकिन न्यायिक समिति ने सवाल को खुला छोड़ दिया क्योंकि उस मामले में इसका फैसला करना आवश्यक नहीं था।

(1) मुद्दुम बनाम राम 6 डब्ल्यू. आर. 71 (2) नागलिंगम बनाम राम चंद्र, आई.एल.आर. 24 मद्रास 429 (3) भागवत बनाम एमएसटी कपूरनी, आई.एल.आर. 23 पटना 599 (4) लाला मुक्ति प्रसाद बनाम श्रीमती ईश्वरी, 24 सी.डब्ल्यू.एन. 938 (5) जुगमोहन दास बनाम सर मंगल दास, 10 बॉम्बे 528 (6) परसोतम बनाम जानकी बाई, आई.एल.आर. 29 इलाहाबाद 354; अमरनाथ बनाम गुरन, ए.एल.आर. 1918 लाह 394(7) 64 आई.ए. 265 इस स्थापित कानून को ध्यान में रखते हुए कि एक मिताक्षर पिता को अपनी स्व-अर्जित संपत्ति पर निपटान का पूर्ण अधिकार है, जिसमें उसके पुरुष वंशजों द्वारा कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, हमारी राय यह है कि एक बेटे को विरासत में दी गई या उपहार में दी गई ऐसी संपत्ति को आवश्यक रूप से, और सभी परिस्थितियों में, पैतृक संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए जिसमें उसके बेटे समन्वित ब्याज प्राप्त करेंगे। इस चरम दृष्टिकोण का, जिसे ऊपर निर्दिष्ट कलकत्ता मामले (1) में निर्धारित किया जाना चाहिए, दो आधारों पर समर्थन करने की कोशिश की जाती है। पहला आधार पैतृक संपत्ति में पिता और पुत्र के समान स्वामित्व का प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे यज्ञवल्क्य के अधिकार पर मित अक्षर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दूसरा आधार यह है कि मिताक्षरा द्वारा दी गई "स्व-अधिग्रहण" की परिभाषा इस चरित्र के एक उपहार को नहीं समझती है और जैसा कि मिताक्षर द्वारा दिया गया है, वह इस चरित्र के किसी भी उपहार को नहीं समझता है और न ही समझ सकता है और इसके परिणामस्वरूप ऐसा उपहार आंशिक संपत्ति हो सकता है जैसा कि दाता और उसके बेटों के बीच होता है। जहां तक कि पहला आधार चिंतनीय है, पैतृक संपत्ति में पिता और

पुत्र के शाश्वत स्वामित्व के सिद्धांत की नींव याज्ञवल्क्य (2) का प्रसिद्ध पाठ है जिसमें कहा गया हैः "दादा के अधिग्रहण में पिता और पुत्र का स्वामित्व समान है, चाहे वह भूमि, कोरोडी या चल सम्पत्ति हो।"

यह ध्यान देने योग्य है कि विज्नेश्वर ने अपनी रचना के अध्याय I, धारा 5 में इस अंश का आह्वान किया है, जिसमें वह अपने पोते के बीच दादा की संपत्ति के विभाजन से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि पोते-पोतियों का दादा की संपत्ति में जन्म से बेटों के साथ समान अधिकार होता है और परिणामस्वरूप वे विभाजन पर शेयरों के हकदार होते हैं, हालांकि उनके हिस्से प्रति व्यक्ति नहीं बल्कि प्रति वर्ग के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इस चर्चा का वर्तमान प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है। यह निर्विवाद रूप से सच है कि मिताक्षरा के अनुसार, बेटे को अपने पिता और दादा की संपत्ति दोनों में जन्म से अधिकार है, जैसा कि पहले बताया गया है, इस संबंध में मिताक्षरा द्वारा ही एक अंतर किया गया है।

(1) मुद्दुन बनाम राम, 6 डब्ल्यू. आर. 71 के माध्यम से। (2) याज्ञवल्क्य के माध्यम से, पुस्तक 2, 12 पिता के हाथों में पैतृक या दादा की संपत्ति, बेटे को अपने पिता के साथ समान अधिकार हैं; जबकि पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में, उसके अधिकार असमान हैं क्योंकि पिता के पास उस पर स्वतंत्र शक्ति या प्रमुख हित है (1)। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि बेटा पिता के साथ इस समान अधिकार का दावा तभी कर सकता है जब दादा की संपत्ति उसके पिता को हस्तांतरित हो गई हो और उसके हाथों में पैतृक संपत्ति बन गई हो। दादा की संपत्ति आम तौर पर पिता में पैतृक संपत्ति के रूप में निहित हो सकती है यदि और जब पिता दादा की मृत्यु पर ऐसी संपत्ति विरासत में प्राप्त करते हैं या इसे विभाजन द्वारा प्राप्त करते हैं, जो दादा ने स्वयं अपने जीवनकाल के दौरान बनाई थी। इन दोनों अवसरों पर दादा की संपत्ति पिता के पुत्र या वंशज के रूप में उनके कानूनी अधिकार के आधार पर पिता के पास आती है और

परिणामस्वरूप यह उनके हाथों में पैतृक संपत्ति बन जाती है। लेकिन जब पिता उपहार के रूप में दादा की संपत्ति प्राप्त करता है, तो वह इसे इसलिए प्राप्त नहीं करता है क्योंकि वह एक बेटा है या उस संपत्ति पर उसका कोई कानूनी अधिकार है, बल्कि इसलिए कि उसके पिता ने उस पर एक अनुग्रह करने का विकल्प चुना जो वह किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकता था। ऐसी संपत्ति में वह जो ब्याज लेता है, वह अनुदानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। हम सोचते हैं कि इस भेद को ध्यान में न रखने से बहुत भ्रम पैदा हुआ है। यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति के हाथों में पैतृक है या नहीं, न केवल मूल और वर्तमान धारक के बीच संबंध बल्कि संचरण के तरीके को भी देखा जाना चाहिए; और संपत्ति को आम तौर पर केवल तभी पैतृक माना जा सकता है जब वर्तमान धारक को यह उसके मूल मालिक के बेटे या वंशज होने के कारण मिला हो। हमारा मानना है कि मिताक्षर इस मुद्दे पर काफी स्पष्ट है। इसने पिता के उपहारों को पूरी तरह से एक अलग श्रेणी के तहत रखा है और एक से अधिक स्थानों पर उन्हें विभाजन से मुक्त घोषित किया है। इस प्रकार अध्याय 1, धारा 1, प्लेसिटम 19 मिताक्षर में नारद के एक पाठ का उल्लेख किया गया है जो कहता हैः (1) मईन के हिंदू कानून, 11 वें संस्करण, पृष्ठ 336 के माध्यम से, "वीरता से जो प्राप्त होता है उसे छोड़कर, एक पत्नी की संपत्ति और विज्ञान द्वारा जो अर्जित किया जाता है जो तीन प्रकार की संपत्ति है जो विभाजन से मुक्त है; और एक पिता द्वारा प्रदान किया गया कोई भी अनुग्रह। मिताक्षर का अध्याय ।, धारा 4 विभाजन के लिए उत्तरदायी प्रभावों से संबंधित है और संपत्ति "1, पिता के अनुग्रह के माध्यम से प्राप्त" उन चीजों की सूची में एक स्थान पाती है जिनके लिए कोई विभाजन निर्देशित नहीं किया जा सकता है (1)। इस पर अध्याय । की धारा 6 में जोर दिया गया है जिसमें एक पिता द्वारा दिए गए अनुग्रह पर चर्चा की गई है। विभाजन के बाद पैदा हुए मरणोपरांत पुत्रों या पुत्रों के अधिकार। धारा के 13 वें खंड में कहा गया है कि भले ही

विभाजन के बाद पैदा हुआ बेटा अपने पिता और मां की पूरी संपत्ति ले लेता है, फिर भी अगर पिता और मां ने अलग हुए बेटे को कुछ संपत्ति दी है, तो वह उसके पास ही रहना चाहिए। यज्ञवल्क्य के एक ग्रंथ में तब उद्धृत किया गया है कि "पिता और माता द्वारा दिए गए प्रभाव उसी के हैं जिसे वे प्रदान किए गए हैं" (2)। यह ध्यान दिया जा सकता है कि "पिता के अनुग्रह से प्राप्त" (पितृ प्रसाद लाभ) अभिव्यक्ति जो मिताक्षर की धारा 28, धारा 4 में पाई जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक मिताक्षर पिता अपने बेटों की सहमति के बिना भी जब चाहे अपने हाथों में पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति दोनों का विभाजन कर सकता है; लेकिन अगर वह विभाजन करने का विकल्प चुनता है, तो उसे कानून में निर्धारित निर्देशों के अनुसार इसे करना होगा। यहां तक कि असमानता की सीमा, जो सबसे बड़े और छोटे बेटों के बीच अनुमत है, पाठ (3) में इंगित की गई है। कुछ भी उसके अपने पक्ष या विवेक पर निर्भर नहीं करता है। हालाँकि, जब वह कोई उपहार देता है जो केवल अनुग्रह का कार्य है, तो वह किसी भी नियम या कानून के आदेश द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करने में निरंकुश होता है। पिता की कृपा से प्राप्त इन उपहारों में ही विज्नेश्वर, पूर्व ऋषियों का अनुसरण करते हुए, पुत्रों के अनन्य अधिकार की घोषणा करता है।

(1) मिताक्षर की धारा 4, स्थान 28 के माध्यम से। (2) याज्ञवल्क्य 2,124 के माध्यम से। (3) मिताक्षर अध्याय I, खंड 2 के माध्यम से।

इसलिए, हमारा मानना है कि यह कहने के लिए कोई अधिकार नहीं है कि मिताक्षर के अनुसार, पिता द्वारा बेटे को एक स्नेही उपहार, यदि वास्तव में ऐसा है, तो दानकर्ता के हाथों में पैतृक संपत्ति है। यदि यह सही दृष्टिकोण है, जैसा कि हम सोचते हैं, तो यह ऊपर बताए गए अन्य तर्क का पूरा जवाब देगा कि ऐसी उपहार में दी गई संपत्ति को पिता और पुत्रों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए क्योंकि यह मिताक्षर द्वारा दी गई "स्व-अधिग्रहण" की परिभाषा में नहीं आता है। उनके काम के अध्याय I,

धारा 4 में, विज्नेश्वर उन संपत्तियों की गणना और उनसे संबंधित है जो विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। खंड का पहला स्थान परिभाषित करता है कि "स्व-अधिग्रहण" क्या है। यह परिभाषा याज्ञवल्क्य के पाठ पर आधारित है कि "जो कुछ भी सह-भागीदार द्वारा स्वयं किसी मित्र से पिता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना या विवाह के समय उपहार के रूप में प्राप्त किया जाता है, वह सह-उत्तराधिकारियों से संबंधित नहीं है।" यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि पिता के उपहार को पिता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना बेटे द्वारा अर्जित नहीं कहा जा सकता है, इसलिए इसे ऊपर दी गई परिभाषा के अर्थ में बेटे का स्व-अधिग्रहण नहीं माना जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप इसे विभाजन से छूट नहीं दी जा सकती है। यह तर्क हमें असमर्थनीय लगता है। मिताक्षर के पहले अध्याय की धारा 4 में संपत्ति की विभिन्न वस्तुओं की गणना की गई है, जो लेखक के अनुसार, विभाजन से मुक्त हैं और स्व-अधिग्रहण उनमें से केवल एक है। पिता के उपहार छूट सूची में एक और वस्तु का गठन करते हैं जिसका विशेष रूप से खंड के स्थान 28 में उल्लेख किया गया है। हम मईन के हिंदू कानून के नवीनतम संस्करण में व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं कि पिता का उपहार अपने आप में एक अपवाद है, प्लेसिटम 28 में प्रावधान को इस आवश्यकता के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि उपहार पिता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना भी होना चाहिए, क्योंकि यह कहना एक स्पष्ट विरोधाभास होगा कि संपत्ति को नुकसान पहुँचाए बिना संपत्ति से कोई भी उपहार पिता द्वारा दिया जा सकता है। खंड के प्लेसिटम 1 और प्लेसिटम 28 के बीच वास्तव में कोई विरोधाभास नहीं है। दोनों छूट प्राप्त संपत्तियों की अलग और स्वतंत्र वस्तुएं हैं, जिनका कोई विभाजन नहीं किया जा सकता है। (1) मईन का हिंदू कानून, 11वां संस्करण, पैराग्राफ 280, पृष्ठ 344 देखें।

इस संबंध में एक अन्य तर्क पर जोर दिया गया है, जिसे पटना उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों का समर्थन मिला है, जिन्होंने ऊपर निर्दिष्ट पूर्ण पीठ मामले (1)

का फैसला किया था। ऐसा कहा जाता है कि पिता के उपहार के संबंध में अपवाद जैसा कि प्लेसिटम 28 में निर्धारित किया गया है, केवल दाता और उसके भाइयों के बीच विभाजन का संदर्भ है, लेकिन जहां तक दाता के पुरुष मुद्दे का संबंध है, यह अभी भी आंशिक है। हमारी राय में यह तर्क सही नहीं है। यदि स्व-अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान सभी विभाजनों पर लागू होता है, चाहे वह संपार्श्विक के बीच हो या पिता और उसके बेटों के बीच, तो इसका कोई कल्पनीय कारण नहीं है कि प्लेसिटम 28, जो एक ही अध्याय में आता है और एक ही विषय से संबंधित है, विभाजन के सभी मामलों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए और केवल संपार्श्विक तक ही सीमित होना चाहिए। यह भेद करने का कारण निस्संदेह पैतृक संपत्ति में पिता और पुत्र के बीच समान स्वामित्व का सिद्धांत है, जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और जो हमारी राय में पिता के उपहारों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। इसलिए, हमारा निष्कर्ष यह है कि एक पिता द्वारा अपने बेटे को उपहार में दी गई संपत्ति केवल इस तथ्य के कारण नहीं बन सकती कि उसे अपने पिता या पूर्वज से मिली थी। जैसा कि कानून स्वीकार करता है और अच्छी तरह से ज्ञात है कि एक मिताक्षर पिता के पास अपनी स्व-अर्जित संपत्ति पर स्वभाव की पूरी शक्तियां होती हैं, यह एक आवश्यक परिणाम के रूप में नहीं है कि पिता स्पष्ट रूप से प्रदान करने के लिए काफी सक्षम है, जब वह कोई उपहार देता है, या तो जे दाता इसे विशेष रूप से अपने लिए लेगा या यह कि उपहार परिवार की अपनी शाखा के लाभ के लिए होगा। यदि उपहार के विलेख या वसीयत में इस आशय के स्पष्ट प्रावधान हैं, तो कोई कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना नहीं है और ऐसी संपत्ति में बेटा जो ब्याज लेगा, वह अनुदान की शर्तों पर निर्भर करेगा।

हालाँकि, यदि ऐसा कोई स्पष्ट शब्द नहीं है जो यह वर्णन करता है कि दाता को किस तरह का ब्याज लेना है, तो प्रश्न निर्माण का होगा और अदालत को निर्माण के प्रसिद्ध नियमों के अनुसार आसपास की परिस्थितियों के साथ लिए गए दस्तावेज़ की

भाषा से दाता के इरादे को एकत्र करना होगा। निश्चित रूप से स्वभाव के सार पर जोर दिया जाना चाहिए, न कि उसके मात्र रूप पर। अदालत को ऐसे मामलों में जो भौतिक प्रश्न तय करना होगा, वह यह है कि क्या दस्तावेज़ और सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि दाता अपने लाभ पर इनाम देने का इरादा रखता था और जो उसके द्वारा उसकी खुशी पर निपटा जा सकता था। या यह कि स्पष्ट उपहार विभाजन की योजना का एक अभिन्न अंग था और जो बेटे को दिया गया था वह वास्तव में उस संपत्ति का हिस्सा था जो आम तौर पर उसे और विभाजन पर परिवार की उसकी शाखा में आवंटित किया जाता था। (1) भागवत बनाम एम.एस.टी., (कपूरानी, आई.एल.आर. 23 पटना 599)

दूसरे शब्दों में, सवाल यह होगा कि क्या अनुदानकर्ता वास्तव में अपनी संपत्तियों का उपहार देना चाहता था या उसे विभाजित करना चाहता था। जैसा कि यह पिता के लिए खुला है कि वह अपनी संपत्तियों का उपहार या विभाजन करे जैसा कि वह स्वयं चुनता है, कड़ाई से कहने पर, यह कोई धारणा नहीं है कि उसने एक या दूसरे का इरादा किया था। इन सिद्धांतों के आलोक में हम अब इस मामले के तथ्यों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसके पिता की वसीयत जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1 को अनुसूची बी की संपत्तियों की दो वस्तुएं मिलीं है, एक्सपी-1, 6 जून, 1912 को दिनांकित है। वसीयत एक सरल दस्तावेज है। इसमें कहा गया है कि वसीयतकर्ता की आयु 65 वर्ष है और उसकी सभी संपत्तियां उसकी हैं जो उसने पैतृक निधि के किसी भी केंद्र से प्राप्त नहीं की थीं। उनके तीन बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़ा प्रतिवादी नं 1. मूल रूप से वसीयत में जो प्रावधान है वह यह है कि उनकी मृत्यु के बाद, ए अनुसूची की संपत्तियां उनके सबसे बड़े बेटे को, बी अनुसूची की संपत्तियां उनके दूसरे बेटे को और अनुसूची सी में वर्णित संपत्तियां सबसे छोटे द्वारा ली जाएंगी। बेटों को उन्हें आवंटित संपत्तियों का पूर्ण अधिकारों के साथ और बेटे से पोते को वंशानुगत रूप से उपहार, विनिमय, बिक्री

आदि जैसे अलगाव के साथ उपभोग करना है। ऐसा लगता है कि वसीयतकर्ता ने पहले ही कुछ संपत्ति अपने दो भाइयों की पत्नियों और अपनी पत्नी को भी दे दिया थाउन्हें अपने प्राकृतिक जीवन की शर्तों के दौरान इन संपत्तियों का आनंद लेना था और उनकी मृत्यु के बाद, वे उनके एक या दूसरे बेटे में निहित होंगे, वसीयत में संकेत दिया गया था, डी अनुसूची संपत्ति को उनके तीसरे बेटे और एक अविवाहित बेटी के विवाह के खर्च के लिए अलग रखा गया था। उसकी पत्नी को इस संपत्ति को बेचने का अधिकार दिया गया था ताकि वह अपनी बिक्री की आय के साथ शादी के खर्चों का भुगतान कर सके। हमें ऐसा लगता है कि आसपास की परिस्थितियों के आलोक में दस्तावेज़ को पढ़ने पर वसीयतकर्ता का प्रमुख इरादा अपने निकट संबंधों के उन लोगों के लिए उपयुक्त प्रावधान करना था जिन्हें वह अपने स्नेह और इनाम पर दावा करने वाला मानता था। वह नहीं चाहते थे कि भविष्य में विवादों से बचने के लिए अपनी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों के बीच उसी तरह बांटा जाए जैसे उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद किया होगा। यदि वसीयतकर्ता ने हिंदू कानून के अनुसार विभाजन पर विचार किया होता, तो वह निश्चित रूप से अपनी पत्नी को एक बेटे के बराबर हिस्सा और अपनी अविवाहित बेटी को एक चौथाई हिस्सा देता। उनके भाइयों की पत्नियां तब चर्चा में नहीं आएंगी और उनकी पत्नी को उनके अविवाहित बेटे और बेटी की शादी के खर्चों को चुकाने के लिए संपत्ति बेचने के लिए अधिकृत किए जाने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। वसीयतकर्ता निश्चित रूप से अपनी संपत्तियों का वितरण इस तरह से करना चाहता था कि निर्विकारता के मामले में क्या होगा। लेकिन हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, वह यह है कि उनके बेटों को उनके लिए बनाई गई संपत्तियों में किस तरह का हित लेना था, इसके बारे में उनका इरादा है। यहाँ वसीयत पूरी तरह से स्पष्ट है और यह स्पष्ट रूप से बेटों को बिक्री, उपहार और विनिमय के माध्यम से अलगाव की पूरी शक्तियों के साथ पूर्ण अधिकार प्रदान करती है। वसीयत में इस बात

का कोई संकेत नहीं है कि वसीयत की गई संपत्तियों को बेटों द्वारा उनके परिवारों या पुरुष मुद्दों के लिए रखा जाना था और हालांकि वसीयत में विभिन्न अन्य संबंधों का उल्लेख है, लेकिन बेटों के बेटों का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है। यह इंगित करता है कि वसीयतकर्ता चाहता था कि उसके बेटों को उन्हें विरासत में दी गई संपत्तियों में पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए और वह अपने परिवारों और बच्चों की देखभाल पूरी तरह से अपने बेटों पर छोड़ने के लिए संतुष्ट था। यह कि वसीयतकर्ता बेटों को वही अधिकार प्रदान नहीं करना चाहता था जो उन्हें निर्विकारता पर हो सकते थे, वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित दो बाद के निरसन उपकरणों द्वारा आगे स्पष्ट किया जाता है। 26 मार्च, 1914 के दस्तावेज़ प्रदर्शनी पी-2 के अनुसार, उन्होंने अपनी वसीयत के उस हिस्से को रद्द कर दिया जिसने उनके सबसे छोटे बेटे को अनुसूची-सी संपत्ति दी थी। चूंकि यह बेटा बुरी संगति में पड़ गया था और अपने पिता की अवज्ञा कर रहा था, इसलिए उसने अपने पक्ष में वसीयत को रद्द कर दिया और अपनी वही संपत्तियां अपने अन्य दो लोगों को इस निर्देश के साथ दे दी कि वे इसमें से अपने सबसे छोटे भाई और दूसरे या उसके परिवार को कुछ रखरखाव भत्ता देंगे यदि वह शादी कर लेता है। 14 अप्रैल, 1914 को एक दूसरा प्रतिसंहरण दस्तावेज, प्रदर्शनी पी-3 निष्पादित किया गया था, जिसके द्वारा पहले का प्रतिसंहरण रद्द कर दिया गया था और सबसे छोटे बेटे को दी जाने वाली संपत्तियों को दोनों भाइयों से छीन लिया गया था और उनके दामाद को दे दिया गया था और उत्तराधिकारी को निर्देश दिया गया था कि जब भी उन्हें विश्वास हो कि बाद वाले ने खुद को ठीक से सुधार लिया है, तो उन्हें तीसरे बेटे को सौंप दिया जाए। हमारी राय में, वसीयत को समग्र रूप से पढ़ने पर यह निष्कर्ष स्पष्ट हो जाता है कि वसीयतकर्ता का इरादा अपने बेटों और पोतों के अधिकारों से किसी भी तरह से बंधे बिना संपत्तियों को अपने स्वयं के अधिग्रहण के रूप में पूर्ण अधिकार में लेना था। दूसरे शब्दों में, उनका इरादा यह नहीं था कि संपत्ति को बेटों द्वारा पैतृक संपत्ति के रूप में

लिया जाए। परिणाम यह है कि अपील की अनुमति दी जाती है, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के निर्णयों और फरमानों को दरकिनार कर दिया जाता है और वादी का मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले में शामिल प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर न्यायिक राय में काफी अंतर था और वादी स्वयं एक दरिद्र है, हम निर्देश देते हैं कि प्रत्येक पक्ष सभी न्यायालयों में अपना खर्च वहन करेगा।

अपील की अनुमति दी गयी है

अपीलार्थी का अभिकर्ताः एस. सुब्रमण्यन।

प्रत्यर्थी सं 1: के लिए अभिकर्ता एम. एस. के. अयंगर।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सुनील कुमार की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।